ई-मार्केट से किसानों को दिलाएं बड़ा बाजार

मंत्री सीतारमण ने किसानों के लिए बाजार पर दिया जोर

यादगीर (कर्नाटक), 5 जून. केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और जिला प्रशासन से किसानों की उपज को ई-कॉमर्स तथा क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक बाजार तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है.

उन्होंने कहा कि डिजिटल बाजारों से जुड़कर किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है. सीतारमण ने यह बात कर्नाटक के यादगीर जिले के

बद्देपल्ली में महिला-नेतृत्व वाले कृषि प्रसंस्करण केंद्र एवं किसान प्रशिक्षण-सह-साझा सुविधा केंद्र के उद्घाटन के दौरान कही.

बद्देपल्ली में स्थापित यह केंद्र कल्याणा कर्नाटक क्षेत्र में कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई किसान-केंद्रित परियोजनाओं की श्रृंखला का पांचवां केंद्र है. इसकी स्थापना नाबार्ड और सांसद क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) के सहयोग से की गई है. इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका संचालन 'बद्देपल्ली महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड' कर रही है, जिसमें 727 महिला सदस्य शामिल हैं. यह क्षेत्र की पहली पूर्णत: महिला-नेतृत्व वाली कृषि प्रसंस्करण इकाई है, जो महिलाओं को उत्पादन से लेकर ब्रांडिंग और विपणन तक कृषि मूल्य श्रृंखला के हर चरण में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है.

वित्त मंत्री ने नाबार्ड से आग्रह किया कि वह इस केंद्र में तैयार होने वाले उत्पादों को ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स मंचों तक पहुंचाने में सहायता करे.

> वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि यादगीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जिले की लगभग 75 प्रतिशत भूमि पर खेती होती है. यह क्षेत्र प्रतिवर्ष करीब 22,500 टन मूंगफली का उत्पादन करता है. नया केंद्र किसानों को कच्ची मूंगफली को भुनी हुई मूंगफली, पीनट बटर, मूंगफली तेल और डी-ऑयल्ड केक जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने की सुविधा देगा. इससे किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी.

ईपीएफओ में यूएएन प्रक्रिया बदली

नई दिल्ली, 5 जून. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाने और उसे एक्टिव करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब यह पूरी प्रक्रिया आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए की जाएगी. यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और इसका मकसद सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है. नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कर्मचारियों को यूएएन बनाने या एक्टिव करने के लिए अपने नियोक्ता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. अब कोई भी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन से घर बैठे यह काम पूरा कर सकेगा. इसके लिए सरकार की उमंग ऐप और आधार फेस आरडी ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

फॉरेक्स रिजर्व से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा- वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत

विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए एफएआर और ईसीबी से जुड़े नए कदमों की घोषणा

नई दिल्ली, 5 जून. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में बनी हुई है.

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद उन्होंने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 682.2 अरब डॉलर के बेहद मजबूत स्तर पर पहुंच चुका है. यह भंडार बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है. गवर्नर ने

कहा कि मजबूत आर्थिक बुनियाद और संतुलित नीतियों के कारण भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है.

संजय मल्होत्रा ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्तता के सभी प्रमुख मानकों पर मजबूत स्थिति में है.

वर्तमान रिजर्व लगभग 11 महीने के आयात को कवर करने में सक्षम है और देश के कुल बाह्य ऋण का 89 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कवर करता है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति भारत की वित्तीय मजबूती और बाहरी जोखिमों का सामना करने की क्षमता को दर्शाती है. उनके अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का यह स्तर निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक अस्थिरता के दौरान अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है.

> आरबीआई ने विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं. गवर्नर ने बताया कि फुली एक्सेसिबल रूट (एफएआर) के तहत अब 15, 30 और 40 वर्ष की अवधि वाली सभी नई सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाएगा. इससे विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में अधिक अवसर मिलेंगे और दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

यूपीआई से पीएफ की निकासी होगी आसान

नई दिल्ली, 5 जून कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्द ही भविष्य निधि निकासी की प्रक्रिया को और अधिक तेज, सरल तथा सुविधाजनक बनाने जा रहा है.

प्रस्तावित यूपीआई आधारित निकासी सुविधा के माध्यम से कर्मचारी अपने पीएफ खाते से धनराशि निकालने की प्रक्रिया को पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पूरा कर सकेंगे. सरकार इस तकनीक का परीक्षण लगभग पूरा कर चुकी है और इसके शीघ्र लागू होने की संभावना है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने ईपीएफओ रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अद्यतन रखने होंगे, क्योंकि छोटी-सी त्रुटि भी दावे के निपटान में देरी का कारण बन सकती है.

कर्मचारियों को सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) की स्थिति की जांच करनी चाहिए. कई बार पासवर्ड भूल जाने, मोबाइल नंबर बदल जाने या खाता निष्क्रिय होने के कारण कर्मचारियों को जरूरत के समय परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यूएएन सक्रिय हो और उससे जुड़ी सभी जानकारियां सही हों.

100 पौधों के साथ डीआरएम ने की शुरुआत

वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल-ऊर्जा संरक्षण एवं प्लास्टिक उन्मूलन पर रहा विशेष फोकस

अहमदाबाद, 5 जून. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वटवा से साबरमती रेलवे स्टेशन के मध्य ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना का शुभारंभ किया. मंडल रेल प्रबंधकश्री वेद प्रकाश ने 100 पौधों का रोपण कर इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की.

अहमदाबाद मंडल द्वारा 15 मई से 5 जून 2026 तक चलाए गए 21 दिवसीय विश्व पर्यावरण दिवस अभियान का समापन आज बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों के साथ हुआ. अभियान के दौरान मंडल भर में 1200 से अधिक पौधे लगाए

गए, जबकि अहमदाबाद एवं साबरमती स्टेशनों पर यात्रियों और नागरिकों के बीच 200-200 पौधों का वितरण किया गया. समापन समारोह के दौरान वटवा स्थित आरपीएफ बैरक परिसर में डीआरएम श्री वेद प्रकाश, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती शेफाली गुप्ता, महिला कल्याण समिति की सदस्याओं, शाखा अधिकारियों तथा रेल कर्मचारियों ने सामूहिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

> डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने कहा कि अहमदाबाद मंडल पर्यावरण संरक्षण, जल एवं ऊर्जा बचत तथा सतत विकास के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि वटवा-साबरमती ग्रीन कॉरिडोर परियोजना रेलवे परिसरों को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी. उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार वटवा से साबरमती तक रेलवे ट्रैक के दोनों ओर नीम, गुलमोहर, अशोक, एरिका पाम इत्यादि जैसे पर्यावरण-अनुकूल एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वृक्ष लगाएंगे.

सोने-चांदी की कीमत में आई बड़ी गिरावट

सोना 1,300 रुपए तक सस्ता हुआ, चांदी 5,600 रुपए तक गिरी

नई दिल्ली, 5 जून हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी की कीमत में 5,600 रुपये से अधिक की गिरावट आई, जबकि सोना 1,300 रुपये तक सस्ता हुआ.

सर्राफा बाजार में भी सोने और चांदी दोनों की कीमतें नीचे गईं. इस बदलाव ने निवेशकों और ग्राहकों की नजरें प्रमुख शहरों के भाव पर केंद्रित कर दी हैं. एमसीएक्स पर 3 जुलाई डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,64,796 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. शुक्रवार को यह शुरुआती कारोबार में 2,60,024 रुपये पर खुली और 5,629 रुपये की गिरावट के साथ 2,59,167 रुपये पर ट्रेड करने लगी. सुबह 10.15 बजे यह 4,260 रुपये की गिरावट के साथ 2,60,536 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई

सोने की बात करें तो 5 अगस्त डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,59,547 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था.

वेकोलि ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस

नागपुर 5 जून. वेस्टर्न कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आज दिनांक 05 जून 2026 को कम्पनी मुख्यालय में वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. हेमंत शरद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में तथा निदेशक बिक्रम घोष, निदेशक तकनीकी आनंदजी प्रसाद, निदेशक तकनीकी संदीप परांजपे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अवसर विशेष पर संचालन समिति के सदस्य एस. एच. बेग एवं एस. आर. गबाले उपस्थित रहे। प्रारंभ में कंपनी के सीएमडी डॉ. हेमंत शरद पांडे ने पर्यावरण ध्वज फहराया. उसके उपरांत वन्दे मातरम तथा कोल इंडिया कॉर्पोरेट गीत बजाया गया. तत्पश्चात सीएमडी डॉ हेमंत शरद पांडे ने कर्मियों को पर्यावरण - संरक्षण एवं संवर्धन की शपथ दिलाई. अपने संबोधन में उन्होंने वेकोलि के कर्मियों से वेकोलि द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत कराते हुए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की अपील. उन्होंने संगठनात्मक कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यक्तिगत प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया.

आईटी और धातु कंपनियों के दबाव से शेयर बाजारों में गिरावट

मुंबई, 05 जून आईटी, धातु और तेल एवं गैस कंपनियों में बिकवाली के कारण शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही.

बीएसई का सेंसेक्स 116.67 अंक (0.16 प्रतिशत) टूटकर 74,243.34 अंक पर बंद हुआ. यह छह अप्रैल के बाद का इसका निचला स्तर है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 49.85 अंक यानी 0.21 प्रतिशत नीचे 23,366.70 अंक पर बंद.

यह इसका भी सात अप्रैल के बाद का निचला स्तर है. वृहत बाजार

में भी बिकवाली हावी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.38 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.06 प्रतिशत लुढ़क गया. निफ्टी आईटी सूचकांक 0.99 प्रतिशत, धातु सूचकांक 1.60 प्रतिशत और तेल एवं गैस सूचकांक 0.48 प्रतिशत नीचे बंद हुआ.

कृषि बीमा कंपनी का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

किसानों के लिए 6.40 करोड़ पॉलिसियां जारी

ग्रामीण भारत में बीमा कवरेज का विस्तार

नई दिल्ली, 05 जून. भारत की प्रमुख और सबसे बड़ी फसल बीमा कंपनी एआईसी ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परिणाम घोषित किए हैं. कंपनी ने इस दौरान मजबूत वित्तीय स्थिति, बेहतर कार्यकुशलता तथा देशभर के करोड़ों किसानों की आजीविका की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है. वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की सॉल्वेंसी मार्जिन 4.42 दर्ज किया गया है, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है.

कंपनी ने ?10,279 करोड़ का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अर्जित किया तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.40 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसियां जारी कीं. इनमें से 4.5 करोड़ से अधिक पॉलिसि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल के तहत किसानों को भौतिक रूप से वितरित की गईं. वर्ष के दौरान कंपनी ने 9,571 करोड़ के दावों का निपटान किया, जिससे 1.75 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला . 31 मार्च 2026 तक कंपनी की नेटवर्थ बढ़कर 9,165 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 885 करोड़ अधिक है. यह कंपनी की निरंतर प्रगति और वित्तीय मजबूती को दर्शाता है.

समाचार विशेष

हिंसा, वर्चस्व की लड़ाई और गुंडागर्दी ...

क्या शुभेंदु बदल पाएंगे बंगाल की राजनीतिक संस्कृति?

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है. सत्ता परिवर्तन के बाद अलग-अलग जिलों से राजनीतिक हिंसा, हमलों और टकराव की खबरें सामने आई हैं. टीएमसी ने दावा किया कि उसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं. पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि हुगली में चंदीतला पुलिस स्टेशन के पास उन पर हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोटें आईं.

पार्टी ने इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर हमले की बात कही और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. टीएमसी हमलों के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रही है और भाजपा ने सभी आरोपों को खारिज किया है. राजनीतिक तनाव के बीच पश्चिम बंगाल में पहले की चुनावी हिंसा से जुड़े मामलों पर भी कार्रवाई जारी है. हाल ही में टीएमसी के पूर्व विधायक खोखन दास को 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया.

पश्चिम बंगाल में भाजपा के आने को सिर्फ सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे राजनीतिक संस्कृति के नए दौर के तौर पर पेश किया जा रहा है. तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन के दौरान भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही कि टीएमसी ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बना डाला है. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों की गूंज दिल्ली तक पहुंचती रही.

कहा जा रहा है कि बंगाल में लंबे समय तक टीएमसी शासन के बाद पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई और संगठनात्मक संतुलन की प्रक्रिया तनाव बढ़ा रही है.

> **अनुशासन लाना जरूरी**
> बंगाल की राजनीति लंबे समय से प्रतिस्पर्धा वाली और बेहद भावनात्मक रही है, जो कई बार हिंसक रूप ले लेती है. इसलिए भाजपा को अपने संगठन के अंदर भी अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी. ये भी याद रखना होगा कि पार्टी ने बदलाव के लिए वोट मांगा था और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल बदलने का वादा था. इसलिए हिंसा को सिर्फ लोगों का आक्रोश कहकर खारिज करने की बजाय जमीन पर शांति और स्थिरता स्थापित करने की कोशिश ही सबसे सटीक जवाब होगा.

कर्नाटक में बढ़ी भाजपा की चिंता

बेंगलुरु. भारतीय जनता पार्टी पूरे भरोसे में थी कि जिस तरह राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े से या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के झगड़े से भाजपा आसानी से चुनाव जीत गई वैसे ही कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की खींचतान में वह जीत जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है.

कांग्रेस आलाकमान ने अपनी ताकत दिखाई और चुनाव से दो साल पहले डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया. सिद्धारमैया के लोगों को भी एडजस्ट कर दिया गया है. हालांकि फिर भी अंदरूनी तनाव रहेगा. भाजपा को इसका फायदा उठाना है. भाजपा के जानकार नेताओं का कहना है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी को अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा.

अभी तक भाजपा सिद्धारमैया के हिसाब से रणनीति बना कर काम कर रही थी. अगर शिवकुमार सीएम नहीं बनते तो भाजपा के लिए सब कुछ आसान रहता. लिंगायत उसके साथ थे और शिवकुमार के सीएम नहीं बनने पर वोक्कालिगा उसके और उसकी सहयोगी जेडीएस के साथ आ जाएंगे. लेकिन अब उसे रणनीति बदलनी होगी. शिवकुमार सबसे बड़ा वोक्कालिगा चेहरा हैं. उनके सीएम बनने के बाद वोक्कालिगा वोट कांग्रेस के साथ और एकजुट होगा. इससे जेडीएस की मुश्किलें बढ़ेंगी. भाजपा को अब जेडीएस की वजह से ज्यादा लाभ नहीं मिलना है. वोक्कालिगा के अलावा अहिंदा समीकरण का दलित और मुस्लिम वोट भी मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ रहेगा. तभी भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी होगी. सिद्धारमैया के हटने के बाद पिछड़ी जातियों खास कर कुरुबा समुदाय में नाराजगी होगी. भाजपा को उसे साथ लेने की रणनीति बनानी होगी.

59 से 169 सीटों तक पहुंचा कमल

निकाय चुनाव में भाजपा की चुपचाप बड़ी छलांग

चंडीगढ़. पंजाब शहरी निकाय चुनावों से निकली सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि आम आदमी पार्टी 1000 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने में असफल रही है, जबकि भाजपा कई नगर निगमों और नगर परिषदों में मेयर तथा चेयरमैन बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है. अगर पिछले एक दशक के स्थानीय निकाय चुनावों पर नजर डालें, तो पंजाब की राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप साफ दिखाई देता है.

पिछले 11 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब की सत्ताधारी पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में 1000 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. खास बात यह है कि यह स्थिति तब बनी जब चुनाव के दौरान विपक्ष ने लगातार गंभीर आरोप लगाए. विपक्षी दलों का आरोप था कि कई नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द किए गए. 63 वार्डों में आप उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए क्योंकि विपक्षी उम्मीदवार नामांकन तक दाखिल नहीं कर पाए. कांग्रेस और अन्य दलों ने आप विधायकों पर विपक्षी समर्थकों को डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए. इसके अलावा पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग, बूथ कैप्चरिंग और विपक्षी उम्मीदवारों पर हमलों जैसी शिकायतें भी सामने आईं. इसके बावजूद आप 1000 सीटों का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार नहीं कर सकी. इसे भगवंत मान सरकार के खिलाफ बढ़ती जन नाराजगी और एंटी-इंकम्बेंसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. कांग्रेस अब भी स्पष्ट नेतृत्व और दिशा के संकट से जूझ रही है, जबकि अकाली दल अभी तक पूरी तरह राजनीतिक पुनरुत्थान नहीं कर पाया है.

विशेष दक्षिण भारत से शुरू हुआ जनरेशन शिफ्ट

अब कांग्रेस नए चेहरों पर जता रही भरोसा

नई दिल्ली. लंबी खींचतान के बाद कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार की ताजपोशी कांग्रेस में लीडरशिप में बदलाव भी है. 77 साल के सिद्धरामैया की जगह लेने वाले शिवकुमार 64 साल के हैं.

पिछले दिनों 46 साल के नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 80 साल पार के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से तुलना होने लगी. तब मीडिया में भाजपा में लीडरशिप में बदलाव की बहुत चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक परिस्थितिजन्य सीमाओं के दायरे में इस बदलाव की राह पर चल रही है. हाल में उसने केरलम में 69 साल के रमेश चैन्नितला और 64 साल के केसी वेणुगोपालन को

नजरअंदाज कर 61 साल के वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया. बेशक सतीशन को पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा सबसे बड़े सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल होना भी बड़ा कारण रहा, लेकिन कांग्रेस अक्सर ऐसी राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए नहीं जानी जाती. राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खरगे को अध्यक्ष बनाने से भी कांग्रेस के 'अतीतजीवी' होने का ही संकेत गया. हालांकि इस फैसले के मूल में कांग्रेस की दूरगामी राजनीतिक रणनीति भी रही. उत्तर और पश्चिम भारत में भाजपा के बढ़ते वर्चस्व के मद्देनजर अपने संकटमोचक दक्षिण भारत पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए सही फैसला है.

आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनाव में जब कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया हो गया, तब भी दक्षिण ने साथ नहीं छोड़ा था. यह भी सच है कि तमाम कोशिशों के बावजूद दक्षिण भारत का मन भाजपा नहीं जीत पा रही. दक्षिण के पास लोकसभा की केवल 131 सीटें हैं, जिससे सत्ता राजनीति की सीमाएं स्पष्ट होती हैं, लेकिन उनमें अपना वर्चस्व बनाना कांग्रेस के लिए अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. इसलिए नेहरू परिवार के बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते समय उम्रदराज खरगे पर दांव लगाने का फैसला गलत हरगिज नहीं था.

> **संगठन में भी नए चेहरे**
> कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना और केरलम में कांग्रेस ने पीढ़ीगत परिवर्तन कर दिया है. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 62 साल के हैं, तो तेलंगाना के रेवंत रेड्डी 56 के. संगठन में भी नए चेहरे नजर आने लगे हैं. आंध्र प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला 46 साल की हैं और मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 52 साल के. अगले साल चुनाव वाले पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन कभी भी संभव है, तो राजस्थान में सचिन पायलट समेत अन्य राज्यों के युवा नेताओं का इंतजार भी जल्द समाप्त होने की उम्मीदें बढ़ी हैं.